नईदुनिया

यूएन में पाकिस्तान का खेल खत्म! पहली बार सुरक्षा परिषद पहुंचा किर्गिस्तान, जर्मनी को लगा बड़ा झटका

न्यूयार्क

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सुरक्षा परिषद की संरचना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। 3 जून 2026 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के कड़े और हाई-प्रोफाइल चुनावों में किर्गिस्तान को सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। एशिया-प्रशांत समूह की इस महत्वपूर्ण सीट पर अब किर्गिस्तान भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की जगह लेगा, जिसका दो साल का कार्यकाल 2026 के अंत में समाप्त हो रहा है। किर्गिस्तान का यह नया ऐतिहासिक कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बनने के बाद यह पहला मौका है जब किर्गिस्तान विश्व की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की मेज पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है।

एशिया-प्रशांत सीट के लिए किर्गिस्तान और फिलीपींस के बीच बेहद कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। पूरे चार दौर की गहन वोटिंग के बाद किर्गिस्तान ने 142 वोटों के भारी बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज की, जबकि फिलीपींस के खाते में महज 49 वोट ही आए। किर्गिस्तान के अलावा आस्ट्रिया, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो, तथा जिम्बाब्वे को भी 2027-2028 के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का नया गैर-स्थायी सदस्य चुना गया है। ये पांचों नए देश साल 2026 के अंत में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे सदस्य देशों- पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को रिप्लेस करेंगे। इस चुनाव में पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के समूह में आस्ट्रिया (131 वोट) और पुर्तगाल (134 वोट) ने बाजी मार ली, जबकि सबसे बड़े दावेदारों में शुमार किए जा रहे जर्मनी (104 वोट) को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसे एक बड़ा राजनयिक झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी देश (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस) वीटो पावर से लैस हैं, जबकि 10 गैर-स्थायी सदस्यों को भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 2 साल के सीमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

न्यूज ब्रीफ

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने परमाणु सामग्री उत्पादन सुविधा केंद्र का दौरा किया

प्योंगयांग (उत्तर कोरिया)/सियोल (दक्षिण कोरिया)। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन ने हाल ही में शुरू की गई एक परमाणु सामग्री उत्पादन सुविधा केंद्र का दौरा किया है। उन्होंने इस अवसर पर देश के परमाणु हथियारों के भंडार को तेजी से मजबूत करने का संकल्प लिया है। किम के साथ पार्टी के प्रमुख अधिकारी भी थे। यह जानकारी गुरुवार को सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) ने दी। केसीएनए ने इस स्थान का खुलासा नहीं किया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के हवाले से इस घटनाक्रम की चर्चा की है। सियोल में रक्षा मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में कहा गया है कि यह सुविधा केंद्र यूरेनियम संवर्धन स्थल हो सकता है। इस समय उत्तर कोरिया के योंगब्योन, कांगसोन और कुसोंग में यूरेनियम संवर्धन सुविधा केंद्र हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह साफ नहीं है कि किम ने क्या किसी चौथे सुविधा केंद्र का दौरा किया। किम ने कहा कि पिछले पांच वर्ष में उत्तर कोरिया की परमाणु सामग्री उत्पादन क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो गई है। यह संभावित खतरे और अप्रत्याशित दीर्घकालिक संकट के समय के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने संकेत दिया कि प्योंगयांग का अपनी परमाणु महत्वाकांक्षा से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि नया केंद्र देश की परमाणु क्षमता को तेजी से उन्नत करने की दिशा में मील का पत्थर हुआ है।

फ्रांसीसी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों की फांसी की सजा बरकरार

लाहौर। पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने देश के सबसे चर्चित और झकझोर देने वाले सामूहिक दुष्कर्म मामलों में से एक में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने फ्रांसीसी मूल की महिला के साथ उसके तीन मासूम बच्चों के सामने गैंगरेप करने वाले दो मुख्य दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने दोनों दोषियों आबिद अली और शफकत अली की उस अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले, साल 2021 में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने इन दोनों को दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर अब हाई कोर्ट ने भी अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। यह खौफनाक वारदात 9 सितंबर 2020 की रात को सियालकोट-लाहौर मोटरवे पर हुई थी। फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त पाकिस्तानी मूल की एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ कार से सफर कर रही थी, तभी अचानक उसकी गाड़ी का ईंधन (पेट्रोल) खत्म हो गया। महिला ने सुरक्षा के लिहाज से कार के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं और सड़क किनारे मदद का इंतजार करने लगी। इसी दौरान आबिद और शफकत वहां पहुंचे।

सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती

इस्लामाबाद। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने दियामर-भाशा बांध

परियोजना को जल्द पूरा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए इसे पाकिस्तान की जल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। दियामर में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर लगाए गए अस्थायी रोक संबंधी कदम की आलोचना की और इसे पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बताया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी जल भंडारण और ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से आग्रह किया कि दियामर-भाशा बांध परियोजना को प्राथमिकता देते हुए इसके निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। उनके अनुसार यह परियोजना न केवल बिजली उत्पादन बढ़ाएगी बल्कि कृषि क्षेत्र को भी लाभ पहुंचाएगी। दियामर-भाशा बांध पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में निर्माणाधीन एक बड़ी जलविद्युत परियोजना है। लगभग 4,500 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 15 अरब डालर बताई जाती है। पाकिस्तान का दावा है कि इसके पूरा होने से जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी और लाखों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी।

कूटनीतिक चक्रव्यूह में घिरने के बाद भारत के आगे गिड़गिड़ाया तुर्की

अंकारा

वैश्विक भू-राजनीति में भारत का रणनीतिक प्रभाव इस कदर मजबूत हुआ है कि कभी खुलकर विरोध करने वाले देश भी अब अपने रुख में नरमी लाने पर मजबूर हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण तुर्की के रूप में सामने आया है, जो लंबे समय तक कश्मीर और आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पाकिस्तान का आंख मूंदकर समर्थन करता आया है। हाल ही में सिंगापुर के रैफल्स होटल में आयोजित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार स्ट्रेटजीक स्टडीज (आईएसएस) के एक कार्यक्रम के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान के बयानों में यह साफ बदलाव देखा गया। उन्होंने भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की वकालत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्की की दोस्ती को भारत के खिलाफ दुश्मनी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

तुर्की के विदेश मंत्री ने वैश्विक मंच से भारत से अपील करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर कोई सीधा विवाद नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि भारत इस मामले को एक अलग नजरिए से देखे और दोनों देशों के पास आपसी फायदे और सहयोग के लिए बहुत से क्षेत्र मौजूद हैं, जिनमें तुर्की आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है।

तुर्की के इन नर्म पड़ते तेवरों के पीछे भारत की वह मजबूत कूटनीति है, जिसने तुर्की को उसके अपने ही क्षेत्र में रणनीतिक रूप से घेर लिया है। इस कूटनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी वजह भारत और साइप्रस के बीच लगातार बढ़ती नजदीकियां हैं। पिछले महीने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया था। उल्लेखनीय है कि तुर्की ने साल 1974 से साइप्रस के एक-तिहाई हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है।

अब रक्षा गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक, साइप्रस अपनी सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए भारत से अत्याधुनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और घातक नागास्त्र-1 सुसाइड ड्रोन खरीदने की गंभीर तैयारी कर रहा है। भारत द्वारा तुर्की के विरोधी देश को सैन्य रूप से सक्षम बनाने के इन संकेतों ने तुर्की सरकार की चिंताओं को बेहद बढ़ा दिया है।

इसके अलावा, पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में

हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आपरेशन सिंदूर चलाया था। उस दौरान तुर्की ने भारत के आतंकवाद विरोधी कदमों की निंदा की थी और पाकिस्तान को सैन्य सहायता और ड्रोन की आपूर्ति की थी। भारत ने इस कूटनीतिक धोखे का जवाब देते हुए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र में तुर्की के धुर विरोधी देशों—ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर अपनी रणनीतिक और सैन्य मौजूदगी को मजबूत कर लिया है, जिसके कारण आज तुर्की खुद को अलग-थलग महसूस कर रहा है।

ईरान ने स्पष्ट किया कहा- हमने नहीं किया कुवैत एयरपोर्ट पर हमला

तेहरान। सीजफायर की घोषणा के बीच कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पहुंचे नुकसान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स (आईआरजीसी) ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि इस एयरपोर्ट को हुआ नुकसान किसी ईरानी हमले के कारण नहीं हुआ है। आईआरजीसी के प्रवक्ता के मुताबिक, यह तबाही दरअसल अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीकी खराबी का नतीजा थी। ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसके सैन्य बलों का कुवैत एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे से कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर, ओमान सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के दावे को लेकर भी दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। ईरान के मीडिया हलकों में दावा किया गया कि ईरानी नौसेना ने ओमान सागर में एक अमेरिकी सैन्य पोत को निशाना बनाया है, जो कथित तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करते हुए ईरानी जलक्षेत्र के बेहद करीब पहुंच गया था। हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सेंटकाम ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ईरान का यह दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। अमेरिकी सैन्य संसाधन समुद्र में पूरी तरह सुरक्षित हैं और बिना किसी बाधा के अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत अपना अभियान चला रहे हैं। इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम को लेकर एक नया समझौता सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक घोषणा की है कि इजरायल और लेबनान युद्धविराम की शर्तों पर पूरी तरह सहमत हो गए हैं।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध अधिकार पर रोक लगाई

वाशिंगटन

अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव) ने बुधवार को 215-208 वोटों से एक समवर्ती प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध करने के अधिकारों पर रोक लगा दी। महत्वपूर्ण यह है कि डेमोक्रेट्स के इस प्रस्ताव का चार रिपब्लिकन ओहियो के प्रतिनिधि वारेन डेविडसन, पेंसिल्वेनिया के ब्रायन फिट्ज़पैट्रिक, मिशिगन के टाम बैरेट और केंटकी के थामस मैसी ने समर्थन किया।

रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान या उसकी सेना या सरकार के किसी भी हिस्से के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई में अमेरिकी सशस्त्र बलों का इस्तेमाल तब तक बंद कर देना चाहिए, जब तक कि युद्ध की घोषणा या बल प्रयोग का अधिकार देने वाला कानून पारित न हो जाए। प्रतिनिधि सभा से पारित यह प्रस्ताव अब सीनेट में जाएगा। सीनेट भले ही इसका समर्थन कर दे, लेकिन एक समवर्ती प्रस्ताव में कानून जितना वजन नहीं होता और इसे राष्ट्रपति के सामने पेश नहीं किया जाता, न ही इस पर राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार लागू होता है।

मतदान के बाद हाउस की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेट ग्रेगरी मीक्स ने पत्रकारों से कहा, कांग्रेस ने आज संविधान का पालन किया है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने कहा कि अब बहुत हो चुका। अब इस युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। अब राष्ट्रपति को अमेरिकी लोगों को यह बताने का समय आ गया है कि हम इस युद्ध में क्यों शामिल हुए।

युद्ध शुरू होने के बाद से यह चौथी बार है जब हाउस में डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले ईरान युद्ध अधिकार प्रस्ताव पर मतदान हुआ। वोटिंग से पहले स्पीकर माइक जानसन ने कहा, मुझे लगता है कि इस समय प्रशासन और कमांडर-इन-चीफ से बातचीत करने का अधिकार छीन लेना एक बहुत ही खतरनाक कदम होगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रस्ताव छह रिपब्लिकन सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण पारित हुआ है। इस अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप कमांडर-इन-चीफ के तौर पर अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना जारी रखेंगे, और साथ ही कांग्रेस के प्रति पूरी तरह पारदर्शी भी रहेंगे।

सीमा विवाद पर घिरे नेपाली पीएम शाह, जेन-जी मांग रहा इस्तीफा

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन शाह) के एक विवादास्पद बयान ने देश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल ला दिया है। जिस युवा पीढ़ी और जेन-जी वोटर्स ने पिछले साल पारंपरिक राजनीतिक दलों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके बालेन शाह को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया था, आज वही युवा उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। काठमांडू सहित नेपाल के कई प्रमुख हिस्सों में उनके खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देश के बड़े छात्र संगठनों के एक शक्तिशाली गठबंधन ने प्रधानमंत्री के इस बयान को सीधे तौर पर राष्ट्रविरोधी करार देते हुए राजधानी काठमांडू की सड़कों पर विशाल मशाल जुलूस निकाला है। इस भारी राजनीतिक विवाद की मुख्य वजह प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा संसद में भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर दिया गया एक बयान है। उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा सीमा विवाद पर बोलते हुए कहा कि जिस तरह भारत ने नेपाल की जमीन पर कब्जा किया है, ठीक उसी तरह नेपाल ने भी भारत की जमीन दबा रखी है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए ब्रिटेन और चीन जैसे तीसरे देशों से मदद लेने की वकालत भी कर डाली। प्रधानमंत्री के इस बयान ने नेपाल के राष्ट्रवादी खेमे और युवाओं को बुरी तरह भड़का दिया है।

फाइनल सी-ट्रायल पर निकला रूस का न्यूक्लियर पावर्ड जंगी जहाज

मास्को

समंदर के रास्ते से एक ऐसी खबर आ रही है, जिसने वैश्विक महाशक्तियों की नींद उड़ा दी है। रूस ने करीब 30 साल बाद अपने एक बेहद शक्तिशाली दैत्य को समंदर में उतार दिया है, जो अकेले ही किसी भी आधुनिक नौसैनिक बेड़े को पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखता है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जंगी जहाज एडमिरल नाखिमोवको अपने फाइनल सी-ट्रायल (अंतिम समुद्री परीक्षण) के लिए रवाना कर दिया है। समंदर का यह सुल्तान इतना खतरनाक है कि इसके सामने आने के बाद विरोधी जहाजों को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा।

रूस का यह कीरोव-क्लास क्रूजर कोई आम लड़ाकू जहाज नहीं है। यह वर्तमान में दुनिया का इकलौता और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड काम्बैट शिप (परमाणु संचालित युद्धपोत) है, जिसका कुल वजन करीब 28,000 टन है। इसके विशाल आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अकेला जहाज अमेरिका के तीन सबसे आधुनिक अर्ली बर्क क्लास डिस्ट्रायर जहाजों से भी बड़ा और भारी है। सोवियत संघ के जमाने का यह महादानव पिछले तीन दशकों से अत्याधुनिक अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा था।

अगस्त 2025 में इसने पहली बार अपनी खुद की ताकत से समंदर की लहरों को चीरना शुरू किया था और अब साल 2026 में यह अपनी अंतिम परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सेवेर्नोए डिजाइन ब्यूरो के मुताबिक, इस जहाज को इस तरह अपग्रेड किया गया है कि यह आज की तारीख में दुनिया का सबसे ताकतवर काम्बैट शिप बन चुका है। हालांकि, यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के कारण लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और भारी बजट संकट की वजह से रूस को इसके जुड़वां जहाज प्योत्र वेलिकी को समय से पहले ही रिटायर करना पड़ा, क्योंकि दोनों जहाजों का रखरखाव रूसी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा था। साल 2022 में यूक्रेन के एक हमले में रूस का प्रसिद्ध मोस्कवा जहाज डूब गया था, जिससे रूसी नौसेना की साख को झटका लगा था। अब एडमिरल नाखिमोव को सीधे रूस के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक बेड़े में शामिल किया जा रहा है, ताकि वह अमेरिका और नाटो देशों के किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब दे सके।

176 मिसाइल लान्च सेल्स लगाए गए

इस महाविनाशक जहाज के भीतर हथियारों का ऐसा जखीरा मौजूद है कि कोई भी दुश्मन इसके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस जहाज में कुल 176 मिसाइल लान्च सेल्स लगाए गए हैं। इनमें से करीब 100 सेल्स में रूस के सबसे आधुनिक और अचूक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का नेवल (नौसैनिक) वर्जन तैनात किया गया है, जो आसमान से आने वाली हर आफत को रोक सकता है। इसके अलावा, बाकी बचे सेल्स में रूस की सबसे घातक जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भरी गई हैं। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेजी (मैक 9) से उड़ान भरती है और 1,000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को संभलने का एक सेकेंड का मौका भी नहीं देती।

यूरोप में बढ़ता स्वास्थ्य संकट: तीन साल में 80 हजार नए एचआईवी मामले और 9 हजार टीबी मौतों की आशंका

हर साल लगभग 59 हजार लोगों की मौत

सुरक्षित यौन व्यवहार के प्रति लापरवाही इसके प्रमुख कारण

ब्रुसेल्स

यूरोप में संक्रामक बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। यूरोपीय रोग निवारण एवं नियंत्रण केंद्र (ईसीडीसी) ने चेतावनी दी है कि यदि वर्तमान स्थिति जारी रही तो अगले तीन वर्षों में यूरोप में लगभग 80 हजार नए एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आ सकते हैं, जबकि तपेदिक (टीबी) के कारण 9 हजार से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है।

ईसीडीसी की निदेशक पामेला रेंडी-वैगनर ने कहा कि यूरोप एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि एचआईवी, टीबी और अन्य यौन संचारित संक्रमणों के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। हाल ही में जारी ईसीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में यूरोप में पिछले एक दशक की तुलना में यौन संचारित संक्रमणों की सबसे अधिक दर दर्ज की गई। सिफलिस और गोनोरिया जैसे संक्रमणों के मामलों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता की कमी, समय पर जांच न होना और सुरक्षित यौन व्यवहार के प्रति लापरवाही इसके प्रमुख कारण हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों के साथ-साथ आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नार्वे में संक्रामक रोगों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अनुमान है कि इन देशों में हर साल लगभग 59 हजार लोगों की मौत एचआईवी, टीबी और अन्य यौन संचारित संक्रमणों से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती है। स्वास्थ्य एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में यूरोपीय संघ, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नार्वे में करीब 8 लाख लोग एचआईवी संक्रमण के साथ जीवन बिता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच, प्रभावी उपचार और जागरूकता अभियान इन आंकड़ों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ईसीडीसी ने सदस्य देशों से एचआईवी और टीबी नियंत्रण कार्यक्रमों को मजबूत करने, परीक्षण सुविधाओं का विस्तार करने तथा जोखिम वाले समूहों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अभी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में यूरोप को एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ सकता है।